चीन-पाक आर्थिक गलियारा

चीन-पाक आर्थिक गलियारा

100

से 300 के करीब चीनी कंटेनर परीक्षण के दौरान पहले दिन पाक अधिकृत कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए।

1000

ट्रक हर सप्ताह काराकोरम राजमार्ग से होकर गिलगित-बाल्टिस्तान में प्रवेश करेंगे।

सीपीईसी परियोजना: एक नज़र

लगभग **50** अरब डॉलर की लागत से पूरा होगा गलियारा।

सड़क, रेल और ऊर्जा पर है खास ध्यान।

2030 तक करीब **7** लाख लोगों को इस परियोजना से प्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिलने की उम्मीद जताई गई है।

करीब **3000** किलोमीटर लंबी सड़क के ज़रिये ग्वादर को चीन के काशगर से जोड़ा जाएगा।

14,503 पाक सुरक्षाकर्मी सीपीईसी के निर्माण में कार्यरत, 7,036 चीनी कामगारों की सुरक्षा में लगे।

- परियोजना की सुरक्षा के लिये पाकिस्तान ने ताकत झोंकी, तटरक्षक बल और वायुसेना को भी लगाया।

- सड़क के साथ-साथ रेल लाइन और गैस पाइपलाइन बिछाने का भी प्रस्ताव है।
- शंतार पास, बाबुसर मार्ग और गिलगित-स्कार्दू मार्ग का निर्माण कराने का वादा है।

चीन को लाभ

- पश्चिम एशिया से तेल की सीधी आपूर्ति पाइपलाइन के ज़रिये हो सकेगी।
- भारत से तनाव की स्थिति में अरब सागर पर रणनीतिक बढ़त बना सकेगा।
- भूमध्य सागर के रास्ते होने वाले भारत के व्यापार पर रख सकेगा नज़र।
- चीन के अपेक्षाकृत कम विकसित पश्चिमी क्षेत्रों का हो सकेगा विकास।

विरोध जारी

- परियोजना के लिये खैबर पख्तूनख्वा के हज़ारा डिवीज़न से हटाए जा रहे लोगों ने विरोध किया।
- गिलगित-बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान में भी परियोजना का बड़े पैमाने पर हो रहा विरोध।
- सिंध ने भी इस योजना पर आपत्ति जताई है।

पाकिस्तान पर असर

- आरंभिक आकलनों के अनुसार, पहले ही साल में जीडीपी में 1.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
- सीपीईसी में कई ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनसे बिजली संकट दूर किया जा सकेगा।
- हालाँकि, पीपीपी सांसद सीपीईसी के ज़रिये देश को आर्थिक गुलाम बनाने की आशंका जता चुके हैं।
- अवामी लीग, फाटा वकील संघ, मज़दूर किसान पार्टी आदि इसे सिर्फ पंजाब की योजना बता रहे हैं।

चिंता के बिंदु

- सितंबर 2016 में चीन के एक सरकारी अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' ने परियोजना को चिंतित करने वाला बताया।
- साथ ही सरकार को सलाह दी थी कि वह सीपीईसी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूर्वी एशिया का रुख करे।

भारत की आपत्ति

650 किलोमीटर लंबा हिस्सा सीपीईसी का गिलगित-बाल्टिस्तान से गुज़रेगा, जो भारत का हिस्सा है।

- पाक योजना को मंजूरी देने के लिये अधिकृत नहीं है, रणनीतिक रूप से भी यह भारत के खिलाफ है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के समक्ष आपत्ति दर्ज़ कराई है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/china-pak-economic-corridor